जनसत्ता

मतभेद का हासिल

पिछले कुछ दिनों से जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के भीतर जो चल रहा था, उसका ताजा अंजाम स्वाभाविक ही है। पार्टी के दो महत्त्वपूर्ण नेता प्रशांत किशोर और पवन वर्मा ने कुछ समय पहले संसद में पारित नागरिकता संशोधन कानून पर अपने जो रुख जाहिर किए थे, वे नीतीश कुमार को असहज करने के लिए काफी थे। हालांकि शुरुआती तौर पर यह उम्मीद की जा रही थी कि शायद पार्टी के वरिष्ठ नेता आपस में मिल-बैठ कर इस मसले पर चर्चा से कोई हल निकाल लेंगे, लेकिन दोनों पक्षों के बीच तल्खी का पैमाना बढ़ता गया और आखिरकार जदयू ने प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को पार्टी से निकालने की घोषणा कर दी। यों निकाले गए दोनों नेता भले पार्टी में ऊंची हैसियत रखते थे, लेकिन चूंकि उनका कोई बड़ा जनाधार नहीं था, इसलिए संभव है कि जदयू को उनका साथ छूटने का कोई खास गम न हो। मगर सच यह है कि प्रशांत किशोर और पवन वर्मा ने पिछले कुछ सालों के दौरान पार्टी को जैसा रणनीतिक और बौद्धिक आधार दिया था, उसकी वजह से उन्हें पार्टी के लिए काफी महत्त्वपूर्ण माना जाने लगा था। इस लिहाज से पार्टी से उनका निष्कासन अप्रत्याशित है।

हालांकि दोनों नेताओं के खिलाफ पार्टी की कार्रवाई के जो प्रत्यक्ष कारण दिखते हैं, उससे यही जाहिर होता है कि नीतीश कुमार और इन दोनों नेताओं के बीच मतभेद मुद्दा आधारित था। इसकी शुरुआत केंद्र की भाजपा सरकार की ओर से लाए गए नागरिकता संशोधन कानून पर बिहार सरकार और जदयू का रुख सामने आने के बाद हुई, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएए का समर्थन किया और उनकी सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर तैयार कराने की घोषणा कर दी। दूसरी ओर, प्रशांत किशोर और पवन वर्मा ने साफ लहजे में सीएए और एनपीआर पर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की और अपनी पार्टी के रुख को गलत कहा। इसके बाद मतभेद तल्खी मेंबदल गया। नीतीश कुमार ने एक समय प्रशांत किशोर को जदयू का भविष्य बताया था और माना जा रहा था कि उन्हें आगे पार्टी का नेतृत्व सौंपा जा सकता है। मगर उनके साथ बढ़ती तल्खी के बीच दो दिन पहले नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया कि उन्होंने अमित शाह के कहने पर प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल किया था; जिसे पार्टी में रहना है, रहे, जिसको जाना है, वह जाए। इसके बाद प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, तभी यह लगभग तय हो गया था कि इन नेताओं का साथ रहना अब मुमकिन नहीं है।

सवाल है कि क्या सीएए, एनपीआर और एनआरसी पर अपने विचारों की भिन्नता को पार्टी के भीतर जगह नहीं थी या फिर यह महत्त्वाकांक्षाओं के टकराव का हासिल है? जदयू की समस्या यह है कि राज्य में मुख्य विपक्षी दल राजद ने सीएए, एनपीआर और एनआरसी के मुद्दे पर व्यापक आंदोलन छेड़ा हुआ है और जदयू से निकाले गए ये दोनों नेता इसी मसले पर नीतीश कुमार और उनकी सरकार के खिलाफ सामने आए। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में उभरे थे और जदयू में शामिल होकर उन्होंने मुख्यधारा की राजनीति में अपने पांव रखे थे। इसी तरह पवन वर्मा भारतीय विदेश सेवा से इस्तीफा देकर जदयू में आए और पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद बने। अब दोनों नेताओं को पार्टी से निकाले जाने का क्या असर पड़ता है, यह देखने की बात होगी। खासकर तब, जब इसी साल बिहार विधानससभा के चुनाव भी होने हैं।

हिंसा का प्रदर्शन

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध और समर्थन का सिलसिला इस मुकाम तक पहुंच जाएगा कि विरोध रोकने के लिए समर्थन कर रहे लोग हथियार लेकर सड़क पर उतर आएंगे, शायद यह किसी ने सोचा भी न होगा। एक दिन पहले शाहीनबाग में चल रहे धरने के बीच एक हथियारबंद व्यक्ति घुस आया था और उसने धरने पर बैठे लोगों को धमकी दी। प्रदर्शनकारियों ने उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले किया। इसके अगले दिन यानी वृहस्पतिवार को जामिया मिल्लिया इस्लामिया से राजघाट तक शांतिपूर्वक पदयात्रा निकालने की तैयारी चल रही थी। उसी वक्त एक युवक पिस्तौल लहराते हुए आया और गोली चला दी। गनीमत है, गोली एक युवक की बांह में लगी और वह जख्मी भर हुआ। जिस वक्त यह घटना घटी, वहां सैकड़ों पुलिस कर्मी तैनात थे। गोली चलाने वाले युवक ने वहां पहुंच कर वारदात को अंजाम देने का एलान फेसबुक पर पहले ही कर दिया था। यही नहीं, घटना स्थल पर पहुंच कर उसने अपने को लाइव यानी सीधा प्रसारित भी करना शुरू कर दिया था। वह 'शाहीनबाग, खेल खत्म' जैसे नारे लिख और बोल रहा था। वह जान पर खेल कर वहां पहुंचा था, इसलिए उसने अपने बाद अपने परिवार की हिफाजत की गुहार भी लगाई थी। मगर हैरानी की बात है कि हर वक्त मुस्तैदी का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस वहां हाथ पर हाथ धरे खड़ी तमाशा देख रही थी।

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में करीब दो महीने से शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहे हैं। शाहीनबाग में महिलाओं का प्रदर्शन देश और दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींच रहा है। बहुत सारे लोग उनके समर्थन में रोज जमा हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोग उससे नाराज भी हैं। जाहिर है, पुलिस को वहां किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने की आशंका होनी चाहिए और वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम की उससे अपेक्षा है। मगर एक व्यक्ति का पिस्तौल लेकर उस प्रदर्शन में घुस जाना और धमकाना पुलिस की तैयारियों पर सवाल खड़े करता है। इसी तरह राजघाट तक जाने वाली जिस पदयात्रा की तैयारी चल रही थी, उसके लिए पुलिस को पहले ही सूचित किया जा चुका था। पिछले कुछ दिनों से देश भर में ऐसे प्रदर्शनकारियों पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, उन्हें देखते हुए दिल्ली पुलिस को यहां किसी अप्रिय घटना की आशंका कैसे नहीं रही होगी! फिर कैसे कोई सिरफिरा फेसबुक पर सीधा प्रसारण करते हुए प्रदर्शनकारियों के बीच आकर गोली चला गया और पुलिस चुपचाप खड़ी देखती रही।

इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। पहले जामिया में प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में घुस कर छात्र-छात्राओं पर बर्बरतापूर्वक लाठी चलाने को लेकर उसकी जवाबदेही रेखांकित हुई थी। उसके बाद जब जेएनयू में कुछ अज्ञात हमलावरों ने घुस कर घंटों मार-पीट की और पुलिस गेट पर खड़ी रही, उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया, तब भी उसकी नीयत पर अंगुलियां उठी थीं। अब जामिया के पास रैली की तैयारी कर रहे लोगों पर गोली चलने की घटना ने उसकी साख को चोट पहुंचाई है। छिपा नहीं है कि नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वालों को धमकाने और उन पर हिंसक हमले करने वाले कौन हैं। किसी सरकारी फैसले का शांतिपूर्ण और तार्किक विरोध हर नागरिक का अधिकार है, उसे हिंसक तरीके से रोकने का प्रयास किसी भी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। हालांकि ताजा घटना में पुलिस ने हमलावर युवक को हिरासत में ले लिया गया है, पर इसके लिए पुलिस अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती।

कल्पमेधा

उचित अवसर के अभाव में योग्यता का
मूल्य बहुत कम रह जाता है।
– नेपोलियन

महामारियों की संक्रामक छलांग

संजय वर्मा

जिस तरह से कोई नया वायरस या किसी पुराने संक्रमण का नया रूप अचानक नए संकट के रूप में सामने आ खड़ा होता है, वह हमारे खानपान, रहन-सहन, दवाओं और टीकों की उपलब्धता के अलावा किसी साजिश के संकेत भी देता है। फिलहाल चीन से आए कोरोना वायरस की ही मिसाल लें, तो इसमें लापरवाहियों के अलावा नए प्रयोगों के नाम पर खानपान की बेतुकी शैलियों और चिकित्सा तंत्र में व्याप्त किसी गहरे षड्यंत्र का आभास होता है।

अगर मेडिकल साइंस की बेशुमार तरक्की के बाद भी हर साल दुनिया के किसी न किसी कोने से कोई नया विषाणु हमारे लिए नई चुनौती बन जाता है, तो कहना होगा कि बैक्टीरिया इंसान से भी ज्यादा चालाक है। मध्य चीन के एक करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर वुहान से उभरे कोरोना वायरस के सामने चिकित्सा विज्ञान की आम तैयारियों के चौपट हो जाने का यही मतलब निकलता है। कह सकते हैं कि जिस तरह इंसान ने पृथ्वी पर हर परिस्थिति और वातावरण में ढलना सीख लिया, उसी प्रकार वायरसों ने एंटीबायोटिक्स से समायोजन करना और एक जीव प्रजाति से दूसरी प्रजाति में छलांग लगाना सीख लिया है। कुछ मामलों में तो बैक्टीरिया ने एंटीबायोटिक को नष्ट करने की क्षमता रखने वाले एंजाइम तक बनाने सीख लिए हैं। मगर इसका एक और सच यह है कि महामारी तक बन जाने वाली ऐसी भीषण बीमारियों के प्रसार की रोकथाम न कर पाना हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। यह वक्त ही बताएगा कि दुनिया कोरोना वायरस के पनपने और अचानक विस्फोट करने की इस घटना से कोई सबक लेगी और समस्या का कोई मुकम्मल इलाज खोजेगी या फिर हमेशा की तरह एक वायरस के मंद या खामोश पड़ जाने के बाद कुछ दूसरे नए और पहले से ज्यादा संहारक वायरसों के लिए जमीनें तैयार करती रहेगी।

शुक्र है कि सार्स जैसे लक्षणों वाली कोरोना वायरस से फैलने वाली बीमारी का जनक देश न तो भारत रहा और न ही भारतीयों की बड़ी तादाद इससे प्रभावित हुई। हालांकि पड़ोसी मुल्क चीन में इसके फैलने के बाद ग्लोबल आवाजाही और चीन के मेडिकल कॉलेजों में भारतीय छात्रों की उपस्थिति से हमारी चिंता स्वाभाविक है। इससे थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ताईवान, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और विएतनाम आदि देश भी चिंतित हैं। सभी देशों की चिंता यह है कि उनके कुछ नागरिकों के इस वायरस की चपेट में आ जाने के बाद कहीं ऐसे हालात उनके यहां तो नहीं बन जाएंगे कि हवाई, ट्रेन, बस यातायात रोकना पड़े, शहर खाली कराने पड़ें और रातोरात विशालकाय अस्तपाल बनाने की वैसी ही नौबत आ जाए, जैसी फिलहाल चीन के वुहान शहर में आ गई है।

बीते एक-दो दशक में सार्स, मैड काऊ, इबोला, जीका, बर्ड फ्लू से लेकर स्वाइन फ्लू तक दर्जनों वायरसजनित बीमारियां विश्व पटल पर अपना असर दिखा चुकी हैं। ऐसी स्थिति में यही उम्मीद की जाती रही है कि चिकित्सा तंत्र इन संक्रामक रोगों की रोकथाम में इतना समर्थ हो गया होगा कि इनका कोई तात्कालिक उभार किसी शहर या देश में अचानक पैदा होने वाले आपात हालात पैदा नहीं कर सकेगा। मगर जिस तरह से कोई नया वायरस या किसी पुराने संक्रमण का नया रूप अचानक नए संकट के रूप में सामने आ खड़ा होता है, वह हमारे खानपान, रहन-सहन, दवाओं और टीकों की उपलब्धता के अलावा किसी साजिश के संकेत भी देता है। फिलहाल चीन से आए कोरोना वायरस की ही मिसाल लें, तो इसमें लापरवाहियों के अलावा नए प्रयोगों के नाम पर खानपान की बेतुकी शैलियों और चिकित्सा तंत्र में व्याप्त किसी गहरे षड्यंत्र का आभास होता है।

एक दावा है कि महीने भर के अंदर करीब तेरह सौ लोगों को संक्रमित कर चुके कोरोना नामक वायरल न्यूमोनिया वुहान के एक फूड मार्केट से निकला है, जहां सांपों और चमगादड़ों के मांस से तैयार होने वाली डिश ने कुछ लोगों को अपना मुरीद बना लिया था। खोजबीन से सामने आया तथ्य यह है कि कोरोना वायरस इबोला की तरह चमगादड़ों से ही आया है, लेकिन फर्क यह है कि इसने अपना मौजूदा घातक रूप किसी सांप को संक्रमित करने के बाद धरा है। एक संदेह इस बारे में चीन के खुफिया जैविक हथियारों की फैक्ट्री को लेकर भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वुहान शहर में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में खतरनाक वायरसों पर काम होता है। संभव है कि वहीं से यह वायरस आया होगा। चूंकि चीन एक बंद समाज है, इसलिए इसकी असली वजह का शायद ही कभी खुलासा हो, लेकिन यह तय है कि जिस तरह से एक जीव प्रजाति के संक्रमण दूसरी जीव प्रजाति यानी इंसानों में छलांग लगा रहे हैं, उससे हालात वास्तव में विकट हो चले हैं।

कोरोना से पहले बर्ड, स्वाइन फ्लू और इबोला जैसे वायरसों से जुड़ी यह समस्या सामने आ चुकी है कि इन बीमारियों के वायरस म्यूटेशन (यानी उत्परिवर्तन) का

रुख अपनाने लगे हैं। इसका मतलब यह है कि मौका पड़ने पर वायरस अपना स्वरूप बदल लेते हैं, जिससे उनके प्रतिरोध के लिए बनी दवाइयां और टीके कारगर नहीं रह पाते हैं। पर एक आशंका यह भी है कि कहीं चिकित्सा का वह बाजार ही तो नए वायरसों की पैदावार के पीछे नहीं खड़ा है, जो हरदम ऐसी बीमारियों के दोहन के लिए तैयार रहता है। यह तथ्य अब छिपा नहीं है कि दुनिया में कोई नई बीमारी सामने आती है, तो उसका टीका और दवा बना कर बाजार में लाने पर दवा कंपनियां सैकड़ों-हजारों गुना मुनाफा कमा सकती हैं। इसलिए इस आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे कहीं बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों का ही हाथ हो।

पहले ऐसे कई आरोप लग चुके हैं कि तमाम संक्रामक बीमारियों को लेकर देश-दुनिया में जो हंगामा खड़ा किया जाता है, उनका असली उद्देश्य अरबों-खरबों की फालतू दवाएं गरीब और विकासशील देशों को बेचना होता है। चिकित्सा का यह तंत्र कहीं ज्यादा खतरनाक इंसेफलाइटिस जैसी बीमारियों का सटीक और सस्ता उपचार नहीं खोजता है, जिससे हमारे देश के यूपी-बिहार जैसे राज्यों में हर साल सैकड़ों बच्चों की मौत होती है, लेकिन फ्लू, न्यूमोनिया जैसी संक्रामक और नई बीमारियों को महामारी बताकर एक झटके में अरबों-खरबों डॉलर खींच लेने के इंतजाम कर लेता है। करीब एक दशक पहले हमारे देश में बर्ड फ्लू का खौफ पैदा करके स्विटजरलैंड की दवा कंपनी- रोश से इसकी पेंटेंडेट दवा- टैमीफ्लू के दस लाख कैप्सूल की सरकारी खरीद करवा ली गई थी, लेकिन शायद ही उस दवा का कोई इस्तेमाल हुआ।

वायरसों के रूप बदल लेने और उत्परिवर्तन की क्षमता हासिल कर लेने की हालिया घटनाओं को देखते हुए यह आशंका बेबुनियाद नहीं लगती कि कोरोना को महामारी बनाने के पीछे उद्देश्य बीमारी रोकने से ज्यादा बहुराष्ट्रीय फार्मा कंपनियों की बेहिसाब कमाई के रास्ते खोलना हो।

हालांकि इन आशंकाओं के बावजूद किसी भी नए संक्रामक रोग से निपटने के इंतजामों में ढील देने का कोई संदर्भ नहीं बनता है। हवाई यातायात के कारण चूंकि श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाले संक्रामक रोगों के फैलने की गति बढ़ गई है, इसलिए हर किस्म की सावधानियां बरतने की जरूरत अनिवार्य ही है। यह न भूलें कि हवाई यातायात के कारण संक्रामक रोगों को किसी एक देश की हद तक सीमित रखना काफी मुश्किल हो गया है। एक देश में संक्रमण फैलने के बाद इसकी भरपूर आशंका रहती है कि इसके वायरस आठ-दस घंटे में ही दूसरे देश में पहुंच जाएं। इसलिए हवाई अड्डों पर ही यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग और वायरस से ग्रस्त लोगों को अलग कर उनके अविलंब इलाज की व्यवस्था करना निहायत जरूरी है। पर देखना यह भी होगा कि आखिर हमारा अत्याधुनिक स्वास्थ्य तंत्र ऐसे रोगों को रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा है। सवाल यह भी है कि हर नई बीमारी के प्रसार के मौके पर पूरी दुनिया, खासकर गरीब और विकासशील हांफने क्यों लगते हैं और ज्यादातर बीमारियां यहीं क्यों पैदा हो रही हैं। जिस दिन हमें इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे, कह सकते हैं कि हम तभी खुद को कोरोना जैसे वायरसों से लड़ने और उनसे हमेशा के लिए निजात पाने का कोई जरिया पा सकेंगे।

सलीके की जुबान

मोनिका अग्रवाल

दुनिया मेरे आगे

मर्यादित और संयमित भाषा बोलना भी एक कला है। यह कला मानव जीवन में अहम और माननीय व्यवहार का एक प्रभावी यंत्र है। लेकिन यह कला काम बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। किसी-किसी की भाषा इतनी नीरस और उबाऊ और बोझिल होती है कि या तो सुनने वाला उठ कर चला जाता है या सो जाता है। अनाप-शनाप, बेतुका और बनावटी बोलने का मतलब काम बिगाड़ना है। किसी की भाषा इतनी मधुर और जीवंत होती है कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। किसी ने कहा भी है- 'कुदरत को नापसंद है सख्ती बयान में, इससे नहीं लगाई है हड्डी जुबान में।' लेकिन ऐसा लगता है कि 'बिग बॉस' जैसे टीवी कार्यक्रमों में किसी भी प्रतिभागी की जुबान पर लगाम नहीं। आजकल इस 'रियलिटी शो' में जैसे दृश्य और जैसी अशिष्ट भाषा दिखाई दे रही है, वह औचित्य की हदों को पार कर रही है। अशोभनीय दृश्यों की और गाली-गलौज का पैमाना कुछ इस कदर बढ़ गया है कि एक बड़ी फिक्र दिमाग पर सवार हो जाती है।

ऐसा लगता है कि सब कुछ ताक पर रख दिया गया है। पहले भी टीवी चैनल थे। लेकिन क्या उन पर इस तरह के कार्यक्रम बेलगाम होते थे? 'ह्लबुनियाद' धारावाहिक में नए जमाने की पीढ़ी को भी दिखाया गया था। लेकिन हर चीज को पेश करने, बात कहने का और कुछ भी बोलने का सलीका था। यानी एक मानसिक तौर पर परिपक्व और संयत व्यक्तित्व का तरीका। टीवी देखना किसी का अपना निर्णय है। लेकिन एक सभ्य और मानवीय समाज के लिहाज से कोई मर्यादा होती है। जब हम खुद संयमित आचार-व्यवहार और मधुर भाषा को अपने जीवन में उतारेंगे, तभी हम आने वाली पीढ़ी को कुछ बेहतर दे सकते हैं।

लेकिन सिर्फ मधुर भाषा पर्याप्त नहीं है। 'मुंह में राम बगल में छुरी' जैसी स्थिति भी हो सकती है। इस कला के साथ दूसरी अनेक विशेषताएं और अर्हताएं भी अपेक्षित हैं। यों तो उपदेश देने, सीख देने वालों की कोई कमी नहीं, लेकिन कमी है तो केवल आचरण में लाने वालों की। बोलने का क्षेत्र व्यापक है। इसके अंतर्गत क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कितना, कैसे और कब बोलना है या फिर कब चुप रहना है, सब कुछ आता है। कुछ बातें कुछ तथ्य, कुछ सच्चाइयां इतनी कटु होती हैं कि उन पर अघोषित प्रतिबंध रहता है। जिस बात को बोलने से किसी का आत्मविश्वास टूट जाए, आपस में दूरियां बढ़ जाएं या समाज में वैमनस्यता फैल जाए, ऐसा सच, ऐसी भाषा किस काम की?

हर बात को बोलने की अपनी मर्यादा होती है। इसीलिए कहा गया है कि समय के तराजू पर शब्दों को तोल कर बोलना आवश्यक है। बोलने का ढंग, अंदाज और शैली अपना महत्त्व रखते हैं। उम्र, पद, रिश्ते आदि के कारण शैली में लचीलापन जरूरी है। कुछ अवसर ऐसे भी होते हैं, जब चुप रहना उचित होता है। मौन की भी अपनी एक वाक्शक्ति होती है। कभी-कभी मौन हजार शब्दों पर भी भारी पड़ता है। आज इस दौर में सब ताक पर है। कुछ टीवी चैनलों और कार्यक्रमों की वजह से इस तरह की मर्यादा टूट चुकी है और भाषा का विध्वंस हो रहा है। किसी धारावाहिक को सस्ते प्रेमालाप को बेच कर टीआरपी कमाना है तो किसी धारावाहिक में घर की महिला के घर की ही महिलाओं के लिए साजिशें दिखानी है। किसी चैनल पर हास्य कलाकार अपने शो में भद्दे और द्विअर्थी संवाद परोसने हैं और साथ ही मर्यादित भाषा की पैरवी का पाखंड करते दिख जाएंगे।

लेकिन क्या रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा मधुर और मर्यादित है? बोल तो कोई भी सकता है, लेकिन तरीके और सलीके से, उमंग-तरंग के साथ नपा-तुला, सीधा-साधा बोलना मायने रखता है। व्यक्तित्व विकास के लिए भाषा का महत्त्व तो है ही, पर इसके साथ-साथ वाणी की मधुरता भी उतनी ही आवश्यक है। यह वाणी ही है जिससे किसी भी मनुष्य के स्वाभाव का अंदाजा होता है। चेहरे से अक्सर जो लोग सौम्य या आक्रामक दिखाई देते हैं, असल जिंदगी में उनका स्वभाव कुछ और ही होता है।

भाषा वह है, जिससे संपूर्णता में अभिव्यक्ति हृदय के करीब आभास हो, बुद्धि का प्रकाश, जोश और आत्मीयता हो, न कि निर्जीव अकड़ और मात्र आक्रोश हो। भाषा वह है जिसमें जोश के साथ होश हो। वह नहीं, जिसमें आवाज खटकती हो, चुभती हो। बल्कि वह है जो खनकती हो, रचती हो। भाषा हमेशा संवाद है, सहकार हो, आत्मीयता हो। भाषा का सुनने से भी गहरा संबंध है। जो अच्छा सुन सकता है, बोल भी सकता है। अच्छा सुनने वाला दूसरे की बात को बीच में नहीं काटता। अच्छा सुनने वाला धैर्य और संयम आदि गुण कूट-कूट कर भरे होते हैं। भाषा में अंतर होने से व्यवहार भी अच्छा या बुरा लगने लगता है। इस सृष्टि में ज्यादातर झगड़े वाणी के संयम की कमी और जुबान के गलत प्रयोग के कारण होते हैं। जुबान का सही प्रयोग जहां जरूरी है, भाषा पर पकड़, व्याकरण की शुद्धता और त्रुटिरहित उच्चारण बोलने में चार चांद लगाते हैं।

शिक्षा की सूरत

देश में बच्चों की दशा-दिशा का जायजा लेने वाली प्रतिष्ठित वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट असर- 2019 'अर्ली ईयर्स' ने यह खुलासा किया कि जहां मोबाइल चौरानबे फीसद लोगों के पास है जिनमें साढ़े बावन फीसद के पास स्मार्टफोन है वे इंटरनेट से लैस हैं। पैंसठ फीसद के पास पक्का मकान, छियानबे फीसद के पास बिजली कनेक्शन और उन्यासी फीसद के पास शौचालय है, जबकि केवल दस फीसद परिवार के बच्चों के पास पठनीय सामग्री उपलब्ध है।

यह बहुत दुखद है कि जिस देश को सौ फीसद डिजिटल बनाने की बात हो रही है, वहीं के पूर्व-प्राथमिक स्कूल के बच्चों के पास पाठ्य सामग्री नहीं है। कहा जाता है कि किसी देश के विकास की रीढ़ उस देश की शिक्षा-व्यवस्था होती है। भारत सरकार को इस सर्वे पर विशेष ध्यान देकर शिक्षाविदों का विचार लेकर इसका समाधान जल्द से जल्द करना चाहिए। इस सर्वे में चार से आठ आयु वर्ग के बच्चों के पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय में नामांकन और कुछ महत्त्वपूर्ण विकासात्मक संकेतकों पर बच्चों की क्षमताओं पर जानकारी एकत्रित की गई। इस सर्वे के दौरान देश के चौबीस राज्यों के छब्बीस जिलों में 1514 गांव, 30425 घर और चार से आठ आयु वर्ग के 36930 बच्चों पर केंद्रित है।

यह सर्वे शिक्षा की गुणवत्ता पर भी प्रश्न खड़ा करता है। इसके अनुसार कक्षा पांच के आधे से भी कम छात्र कक्षा दो का पाठ पढ़ पाते हैं। एनसीईआरटी के सीखने के परिणामों के विनिर्देश अनुसार बच्चों को एक में निन्यानबे तक पहचानने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन प्राप्त परिणाम के अनुसार यह औसत बहुत ही कम है। बुनियादी शिक्षा की खराब गुणवत्ता देश की क्षमता पर असर डाल रही है। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार बच्चों को छह वर्ष की आयु में कक्षा एक में प्रवेश लेना चाहिए, लेकिन धरातल पर पांच वर्ष से कम और सात या आठ वर्ष की उम्र के बच्चे कक्षा एक में ज्यादा प्रवेश ले रहे हैं।

सर्वे से हम एक और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन छोटे बच्चों के बीच भी लड़के और लड़कियों के नामांकन पैटर्न अलग-अलग दिखे, जिसमें लड़के निजी और लड़कियां सरकारी संस्थाओं में ज्यादा नामांकित हैं। उम्र के अनुसार या अंतराल बढ़ता जाता है। अंग्रेजी कवि विलियम वड्र्सवर्थ ने कहा है- 'चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन'। लेकिन हम देखते हैं कि पक्के मकान, स्मार्टफोन, अच्छे रहने की सुविधाओं पर खूब जोर दिया जा रहा है, लेकिन बच्चों के पढ़ने की व्यवस्थाओं में बहुत कमी की जा रही है। इसका परिणाम यह होगा कि आने वाले समय में हमारा देश शिक्षा के बहुत ही बुरे स्तरों से गुजरेगा। आज हम विश्व के शीर्ष दो सौ विश्वविद्यालयों में भी अपना स्थान नहीं बना पाए हैं, क्योंकि पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा,उच्चतर शिक्षा की रीढ़ या नींव होती है, इसलिए हमारी सरकार को पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

● *तेज बहादुर मौर्य, बीएचयू, वाराणसी*

जानलेवा वायरस

मध्य चीन में निमोनिया का रहस्यमयी प्रकोप देखने को मिला है, जिसे कोरोनावायरस एनसीओवी से संबंधित बताया जा रहा है। यह एक आरएनए वायरस है जो परिवर्तित और पुनर्संयोजित होकर नए उप भेदों को उत्पन्न करने में सक्षम है। यह कोरोनावायरस की तुलना में सार्क के सबसे ज्यादा नजदीक है। इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि करीब अठारह साल पहले सार्क के कहर से लगभग आठ सौ लोगों की मौत हो गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे 'एनसीओवी 2019' नाम दिया है। इसका संक्रमण बुखार से शुरू होकर सूखी खांसी, उसके एक हफ्ते बाद सांस लेने में कठिनाई तथा गंभीर मामलों में निमोनिया, गुर्दे की विफलता तथा मृत्यु तक हो सकती है।

इसकी शुरुआत चीन के वुहान प्रांत से हुई है, लेकिन यह अब अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान, सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया और नेपाल तक फैल चुका है। इससे अभी तक लगभग सौ लोगों की मौत हो चुकी है और एक हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। चिंता की बात यह है कि इसका कोई प्रभावी टीका अथवा एंटी-वायरस अभी तक उपलब्ध नहीं है। केवल लक्षणों के आधार पर ही इसका उपचार किया जा रहा है। लेकिन इस महामारी से बचने हेतु कुछ सावधानियां बरती जा सकती है। बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, गले में खराश आदि लक्षण होने पर लापरवाही न बरतते हुए तुरंत नजदीकी अस्पताल में जाकर चिकित्सा परीक्षण कराने की जरूरत है।

चीन और नेपाल की सीमा से सटे हुए उत्तराखंड में चंपावत, चमोली तथा पिथौरागढ़ में मेडिकल टीम द्वारा परीक्षण करने का कदम सराहनीय है। साथ ही सात हवाई अड्डों पर चीन से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग का काम भी अच्छा है। इसके अलावा जागरूकता के लिए सरकार को गांवों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कराना चाहिए। विद्यालयों में इसके लक्षण तथा रोकथाम के विषय में बताया जाना चाहिए, क्योंकि एक जागरूक समाज ही किसी महामारी के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

● *कार्तिक त्यागी, शास्त्री नगर, मेरठ*

मानवीयता का तकाजा

भारत में नागरिकता संशोधन कानून पर मचे बवाल के बीच यूरोपीय संसद में भी इस पर बहस के लिए छह प्रस्ताव लाए गए हैं और उस प्रस्ताव को छह सौ से ज्यादा सांसदों ने अपना समर्थन दिया है। यह अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। इसे भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उनकी चिंता भारत की धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को छोड़ कर एक खास धारा की ओर बढ़ने के परिप्रेक्ष्य में है। जाहिर है, यूरोप और देश दुनिया के दूसरे अनेक भागों में करोड़ों लोग संबंधित देशों में अल्पसंख्यकों के तौर पर रहते हैं। अगर भारत के कानून को समर्थन दे दिया जाए तो क्या विश्व के किसी हिस्से में धर्म के आधार पर भेदभाव का विरोध करना नैतिक रह जाएगा? यूरोपीय संसद द्वारा इस मुद्दे पर प्रस्ताव लाए जाने को इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए।

● *नवीन थिरानी, नोहर*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com